सं. ग्रो.वि./रोहतक/128-83/25445.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राज है कि मै. (1) हरियाणा एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, एस.सी.ग्रो. नं० 825-26, सैनटर-22 ए, चण्डीगढ़, (2) हरियाणा एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, रोहतक, के श्रीमक महेन्द्र सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रीद्योगिक विवाद है;

ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते ह्ये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए-एस-ओ. (ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादअस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादअस्त मामला है या उक्त विवाद से मुसंगत या सम्बन्धित मामला है;---

नया श्री महेन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

ैं. श्रो.वि./रोहतक/ ७5-85/25453.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. परल सैरामिक्स वर्कस, नजबगढ़ रोड, बहादुरगढ़ (रोहतक) के श्रमिक श्री राम श्राज्ञा तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले, में कोई श्रौद्योगिक विवाद है;

श्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को नैयायनिर्णय हैतृ निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तायों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी, अधिसूचना सं. 9641-1-अम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.-एस.-ओ.(ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :---

क्या श्री राम श्राज्ञां की सेवाश्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. थो.वि./सोनीपत/210-84/25460.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि प्रेजीडेन्ट पालरी कलां को-भ्रोपरेटिक एण्ड ऋडिट सोसाईटी लि॰, पालरी कलां, (सोनीपत) के श्रमिक अर्जुन सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले म कोई औद्योगिक विवाद है;

श्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, श्रीद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्सयों का प्रयोग करते हुये हिरयाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रिधिसूचना सं 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गिटत सरकारी श्रिधसूचना सं 3864-ए-एस-भ्रो.(ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उवत श्रिधिनियम की धारा 7 के श्रिधीन गिटत श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादशस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निविष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादशस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है;

क्या श्री अर्जुन सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा टीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

जे. पी. रतन, उप संचिव, हरियाणा, सरकार, श्रम विभाग।